

स्टेट ऑफ़ आधार रिपोर्ट

2017-18 रिपोर्ट का सारांश



प्रमुख बिंदु

आधार का दायरा काफी बड़ा है लेकिन इसके डेटा की जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार की गुंजाइश है।

1.5X वोटर आईडी के मुकाबले आधार में 1.5 गुणा ज्यादा गलतियां हैं

वोटर आईडी के 5.7 प्रतिशत के मुकाबले आधार में गलतियों का अनुपात 8.8 प्रतिशत है।

ज़्यादातर भारतीय निजता की परवाह करते हैं, पर विभिन्न सेवाओं को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने पर सहमत भी हैं।

87% ग्रामीण लोगों ने आधार को सरकारी सेवाओं से जोड़े जाने की अनिवार्यता पर सहमति जताई

सेवाओं के लिए यह आंकड़ा 77 प्रतिशत है।

बैंक अकाउंट खुलवाने में आधार के डिजिटल वर्शन (ई-केवाईसी) के मुकाबले हार्ड कॉपी (आधार लेटर) का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है।

17% बैंक अकाउंट होल्डर ने खाता खुलवाने के लिए आधार के डिजिटल वर्शन (ई-केवाईसी) का इस्तेमाल किया

67 प्रतिशत ने आधार लेटर का इस्तेमाल किया और बाकी लोगों ने दूसरे तरह के पहचान पत्र इस्तेमाल किए | यह डेटा नवीनतम बैंक खाते के बारे में है।

आधार की वजह से खाद्य राशन (पी डी एस) के तहत राशन नहीं मिल पाने के मामले काफी ज़्यादा हैं लेकिन यह संख्या गैर आधार वाले कारणों के मुकाबले कम है।

2.2% राजस्थान में राशन के लाभार्थियों को प्रति माह अपना खाद्य राशन आधार से जुड़े हुए कारणों से नहीं मिल रहा है।

यह लगभग 12 लाख लोगों के बराबर है। आधार के अलावा दूसरी वजहों से 6.5 प्रतिशत राशन के लाभार्थियों को प्रति माह अपना खाद्य राशन नहीं मिल रहा है। यह लगभग 37 लाख लोगों के बराबर है।

About IDinsight

IDinsight's mission is to help policymakers and practitioners use rigorous data and evidence to make more socially impactful decisions. We carefully tailor a wide range of quantitative tools to help our clients design better public policies, rigorously test those ideas, and take informed action to improve lives at scale.

IDinsight leads learning partnerships across Asia and Africa, working with governments, multilaterals, foundations, social businesses, and innovative NGOs. We have worked with more than 70 clients across 17 states in India and more than a dozen countries. We work across a range of sectors, including digital ID, education, financial access, governance, health, and sanitation.

We have offices in Dakar, Johannesburg, Lusaka, Manila, Nairobi, New Delhi, San Francisco, and Washington, D.C. To learn more, visit www.IDinsight.org, and follow on Twitter @IDinsight.

About Omidyar Network

Omidyar Network is a philanthropic investment firm. We create opportunity for people to improve their lives by investing in market-based efforts that catalyse economic and social change. In India, we focus our efforts on helping the hundreds of millions of lower-income Indians, from the poorest among us to the existing middle class.

Omidyar Network has committed more than \$1 billion to for-profit companies and nonprofit organisations that foster economic advancement and encourage individual participation across multiple areas, including Digital Identity, Education, Emerging Tech, Financial Inclusion, Governance & Citizen Engagement, and Property Rights.

To learn more, visit www.omidyar.com, and follow on Twitter @omidyarnetwork #PositiveReturns.

Suggested citation

Abraham, Ronald, Elizabeth S. Bennett, Rajesh Bhusal, Shreya Dubey, Qian (Sindy) Li, Akash Pattanayak, and Neil Buddy Shah. *State of Aadhaar Report 2017-18*. Report. IDinsight, 2018.

Comments or questions

We welcome your feedback on this report. Please write to us with your comments or questions to StateofAadhaar@IDinsight.org.

Disclaimer

The information contained in this report is prepared by IDinsight and commissioned by Omidyar Network. It is furnished to the recipient(s) for free distribution and use. The authors have made their best efforts to ensure the accuracy and completeness of the information in this report but make no representations or warranties therein and expressly disclaim any liabilities based on such information or on omissions. Each recipient should therefore conduct her or his own analysis of any information contained in this report.

While Omidyar Network is pleased to sponsor this report, the conclusions, opinions, or points of view expressed in the report do not necessarily represent the views of Omidyar Network.

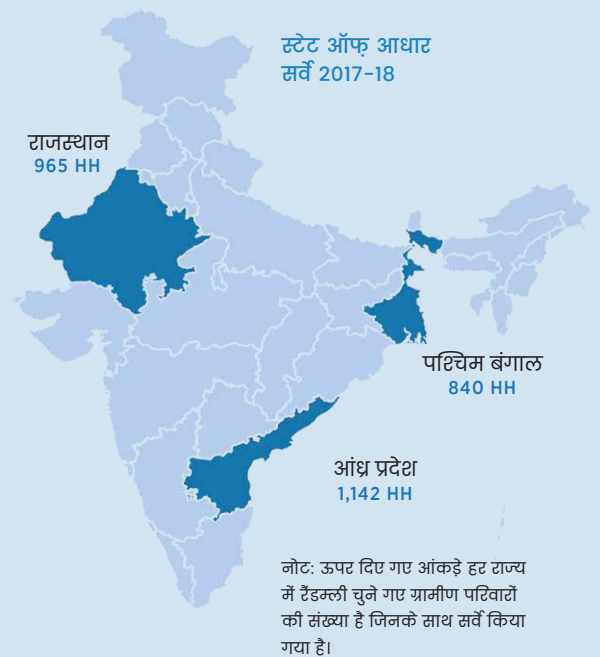
नोट: जब तक खास तौर पर जिक्र नहीं किया जाए, सभी नतीजे हमारे सर्वे पर आधारित हैं और ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं।



परिचय

आधार 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की पहचान सुनिश्चित करता है। इसकी व्यापकता, लोगों को अलग तरह से पहचानने की क्षमता और इसका डिजिटल इंटरफ़ेस इसे पहचान करने का प्रभावी प्लेटफॉर्म बनाता है। हालांकि इसकी यही विशेषताएं, निजता (प्राइवेसी), डेटा की सुरक्षा और लोगों को विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखने जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल आधार पर जो बहस चल रही है, उसके केवल दो पक्ष हैं: या तो इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए या फिर निरंतर तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि, आधार को लेकर हमने तीन राज्यों में जो सर्वे किया (जो अभी तक का सबसे बड़ा सर्वे है), सर्वे के मुताबिक जरूरत है एक तीसरी नज़रिये कि जो बारीकी से मुद्दों का नापतोल कर सके। हमारी रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं, वे बताते हैं कि ऐसा क्यों है।

"स्टेट ऑफ़ आधार" आई डी इनसाइट, एक शोध संस्था, की पहल है। हमारी कोशिश है कि आधार से जुड़ी हर चर्चा और नीति डेटा से प्रभावित हो, न की किसी एक विचारधारा से। यह रिपोर्ट इसी पहल की प्रमुख उपज है और इसका मकसद आधार की स्थिति पर संपूर्ण और ज़मीनी स्तर का आंकलन मुहैया कराना है।



आधार प्लेटफॉर्म

आज आधार बहुत तेज़ी से भारतीय निवासियों की पहचान से जुड़ा दस्तावेज़ बन गया है। इसकी व्यापकता पूरे देश में है और हर जगह इसे समान तौर पर स्वीकार किया जाता है। हमने इस बात की समीक्षा की है कि आधार किन मामलों में उपयोगी साबित हुआ है और कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके साथ ही हमने आगे किस प्रकार के कदम उठाए जायें इसके लिए सुझाव दिए हैं।

1.2 अरब

लोग आधार प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर भारतीय राज्यों में 90 प्रतिशत से ज़्यादा वयस्क इसमें शामिल हैं। (यूआईडीएआई 2018)

27.10 करोड़

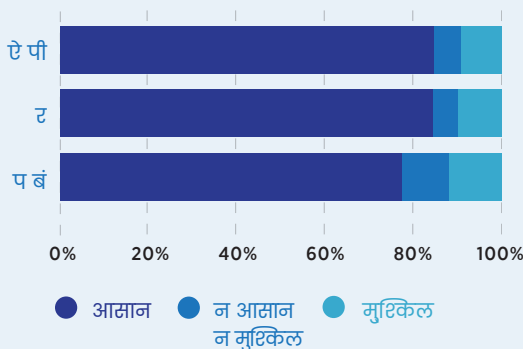
फरवरी 2018 में 27.10 करोड़ लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद की पहचान साबित करने के लिए अपने आधार का इस्तेमाल किया (यूआईडीएआई 2018)। ज़्यादातर लोगों ने आधार कार्ड (के हार्ड कॉपी) का उपयोग किया उसके डिजिटल वर्शन के मुकाबले।

1. क्या उपलब्धियाँ हैं?

ज़्यादातर लोगों के पास आधार नंबर है और लोगों का मानना है कि खुद को आधार से जोड़ना काफी आसान है।

हमने पाया कि नामांकन के लिए लोगों से लिंग, जाति, धर्म या शिक्षा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया।

आधार नामांकन प्रक्रिया के बारे में आम समझ



आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों से गलत तरीके से नामांकन फीस ली गई। हालांकि, राजस्थान में 24 प्रतिशत ने फीस भरी।

2. क्या कठिनाइयाँ हैं?

वोटर आईडी डेटाबेस के मुकाबले आधार डेटा में ज़्यादा गलतियाँ हैं।

वोटर आईडी के मुकाबले आधार में गलतियाँ

	वोटर आईडी में	आधार में
आंध्र प्रदेश	2.4%	8.0%
राजस्थान	2.6%	4.8%
पश्चिम बंगाल	10.4%	12.2%

आधार में गलतियाँ

	नाम	पता	जन्म तिथि
आंध्र प्रदेश	3.8%	1.2%	2.6%
राजस्थान	1.5%	0.7%	2.4%
पश्चिम बंगाल	5.6%	1.7%	3.5%

इसके अलावा, लोगों को खुद को आधार से जोड़ने के मुकाबले अपने आधार को अपडेट करने में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों में ज़रूरत से ज़्यादा फीस जैसी चीज़ें शामिल हैं।

3. कुछ प्रारंभिक सुझाव

आधार डेटा को सही करने के लिए नए अपडेट को लागू करना

आधार डेटा की गलतियों को कम करने के लिए ज़रूरी है कि इससे जुड़े "अपडेट अभियान" चलाए जाएं और कैप लगाए जाएं। ये कैप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आधार नामांकन के कैप होते हैं जिन्होंने पूरे देश में आधार के दायरे को व्यापक बनाने में अहम भूमिका निभाई।

आधार नामांकन और अपडेट प्रक्रिया और फीस की जागरूकता बढ़ाया जाए

वैसे लोगों को फीस, आधार नामांकन और अपडेट प्रक्रिया के बारे में जागरूक बनाया जाए जिन्होंने तय सीमा से ज़्यादा फीस दी। दरअसल, ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि फीस कितनी है। फीस और आधार से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें गलत जानकारी देकर उनका फायदा उठाया जा सकता है।

आधार और वित्तीय समावेशन

ऐसा माना जाता है कि "जन-धन" बैंकिंग योजना, आधार और मोबाइल (इन्हें एकसाथ "जेएम" कहा जाता है) उन लोगों को औपचारिक तरीके से वित्तीय सेक्टर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो या तो बैंकिंग सेवा की सुविधाओं से जुड़े हुए नहीं हैं या जिनके पास ऐसी सेवाओं तक पूरी पहुंच नहीं है। ऐसे दो प्रमुख चैनल हैं जिनके जरिए आधार वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद कर सकता है:

1 आधार लेटर या ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाना।

2 माइक्रो एटीएम और डीबीटी के जरिए अकाउंट के इस्तेमाल को बढ़ाना।

4.8 करोड़ से 13.8 करोड़

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2017-18 के बीच ई-केवाईसी सत्यापन 4.8 करोड़ से 13.8 करोड़ तक बढ़ा है (यूआईडीआई 2018)।

435

सरकारी योजनाएं डीबीटी की मदद से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हैं (कुछ आधार के जरिए), अकाउंट के इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं।

1. क्या उपलब्धियां हैं?

बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार एक सामान्य पहचान-पत्र बन चुका है।

आधार की व्यापकता और इसकी स्वीकृति की वजह से ज्यादातर लोग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, 66.9 प्रतिशत लोगों ने अपने आधार की हार्ड कॉपी का इस्तेमाल किया ना कि ई-केवाईसी का (17.2 प्रतिशत ने ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया)

हाल में बैंक अकाउंट खुलवाने में आधार का इस्तेमाल



- बतौर आईडी आधार का इस्तेमाल किया
- आधार के डिजिटल वर्शन (ई-केवाईसी) का इस्तेमाल किया
- आधार का इस्तेमाल नहीं किया

2. क्या कठिनाइयां हैं?

माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल काफी सीमित है, ई-केवाईसी के जरिए अकाउंट खुलने की प्रक्रिया तेज़ नहीं हो सकती।

सिर्फ 17 प्रतिशत खाताधारकों ने हाल में माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल किया। ई-केवाईसी और पुराने तरीके की केवाईसी के जरिए अकाउंट खुलवाने के वक्त में कोई खास अंतर नहीं है।

जवाब देने वाले ऐसे लोगों की संख्या जिनमें एक दिन के अंदर ही अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा मिल गई



- ई-केवाईसी का इस्तेमाल नहीं किया
- ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया

3. कुछ प्रारंभिक सुझाव

बिज़नेस प्रतिनिधियों (BCs) से जुड़े नेटवर्क को मज़बूत बनाना

फ़िलहाल सिर्फ कुछ लोगों की ही ऑनलाइन बैंकिंग तक पहुंच है और ज्यादातर लोग अभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए बैंक शाखाओं में जाते हैं। माइक्रो एटीएम की सुविधा आसानी से हासिल होने पर इसमें बदलाव आ सकता है। हालांकि, बिज़नेस प्रतिनिधियों (BCs) से जुड़े नेटवर्क को मज़बूत बनाए जाने की ज़रूरत है।

मोबाइल आधारित वित्तीय सेवाओं की ओर कदम बढ़ाना

बिज़नेस प्रतिनिधियों (BCs) का एक स्थायी और टिकाऊ नेटवर्क नहीं होने की सूरत में, मोबाइल आधारित वित्तीय सेवाओं के जरिए बैंक खातों तक पहुंच बनाने का मौका होता है। साथ ही, इसकी मदद से खातों के निष्क्रिय होने संबंधी मामलों में कमी लाई जा सकती है। इन सेवाओं में आधार को पहचान साबित करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

आधार और खाद्य राशन (पी डी एस)

भारत की सामाजिक सुरक्षा योजना की दिशा में आधार को एक प्रमुख सुधार के तौर पर देखा गया है। ऐसा इसलिए कि यह गरीबों को सब्सिडी वाली कीमतों पर खाने-पीने की चीजें खाद्य राशन, काम मिलने की गारंटी (मनरेगा) और अन्य तरह की सुविधाएं मुहैया कराता है। आधार के जो दो प्रमुख उपयोग हैं, वे पिछले साल के दौरान लगातार बढ़े हैं:

1 आधार सीडिंग (डेटाबेस से फर्जी और डुप्लिकेट नामों को हटाने के हेतु)।

2 आधार के जरिए होने वाली बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया (फर्जी लोगों को राशन मिलने से रोकने हेतु)।

72% से 82%

देश के सभी राज्यों में खाद्य राशन के लिए, आधार सीडिंग करवाने वाले लोगों की प्रतिशतता में 72 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी (मुख्य रिपोर्ट में इसका जिक्र है)।

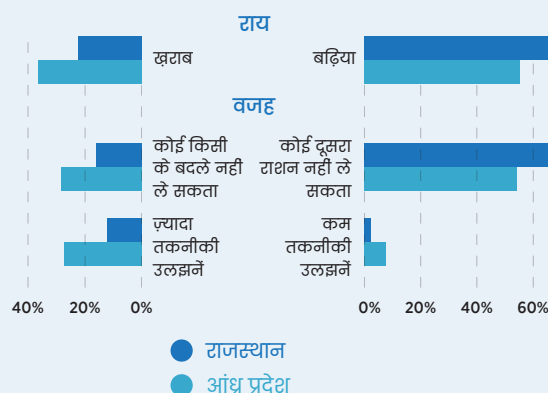
35% से 57%

पूरे देश में ई-पोस (e-PoS) डिवाइस का इस्तेमाल करने वाली पीडीएस दुकानों की प्रतिशतता में 35 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी (लोकसभा 2018)।

1. क्या उपलब्धियां हैं?

लोगों को भरोसा हुआ है कि अब कोई दूसरा शख्स उनका राशन नहीं ले सकता है।

आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ज्यादातर लोग आधार से जुड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था को पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बायोमेट्रिक पहचान की वजह से फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है।



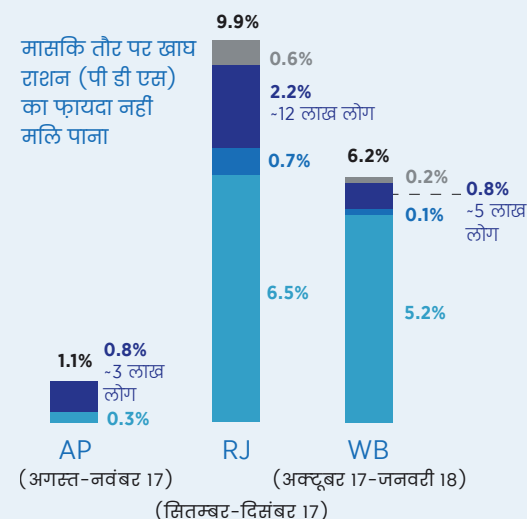
हालांकि, कुछ लोग बायोमेट्रिक सिस्टम को ही खराब मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिस्टम के आने के बाद अब कोई शख्स अपने बदले किसी दूसरे को राशन लेने के लिए नहीं भेज सकता है।

इन मुद्दों पर और विस्तार से जानने के लिए कृपया पूरी रिपोर्ट पढ़ें। रिपोर्ट को डाउनलोड करने, तकनीकी चीजों की जानकारी और हमारी रिसर्च प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.StateofAadhaar.in पर जाएं।

2. क्या कठिनाइयां हैं?

आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पीडीएस का फायदा पाने वाले क्रमशः

0.8 प्रतिशत, 2.2 प्रतिशत, और 0.8 प्रतिशत लोगों को आधार से जुड़े कारणों की वजह से फायदा नहीं मिल पाया। हर महीने ऐसे लोगों की संख्या लगभग 20 लाख है। हालांकि, आधार के अलावा दूसरी वजहों से पीडीएस का फायदा नहीं मिल पाने का अनुपात और ज्यादा है। इसमें राशन नहीं होना जैसी चीजें प्रमुख हैं।



- आधार के अलावा दूसरे कारण
- आधार से जुड़े और आधार के अलावा दूसरे कारण
- सिर्फ आधार से जुड़े कारण
- पता नहीं



3. कुछ प्रारंभिक सुझाव

हर महीने बायोमीट्रिक पहचान व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाए।

उन वैकल्पिक तकनीकों (उदाहरण के लिए, बिना कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए पहचान व्यवस्था) या प्रक्रियाओं (उदाहरण के लिए, सालाना जांच) की मदद ली जाए जो सुरक्षित हैं और आधार संबंधी वजहों से योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाने संबंधी मामलों को कम करती हैं।

ऐसे नियम बनाए जाएं जो वैकल्पिक आईडी या पहचान संबंधी व्यवस्था की अनुमति देते हों।

जो व्यवस्था हो, वह यह सुनिश्चित करे कि आधार की वजह से सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए: इन्हें प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए।

पहचान साबित करने संबंधी अन्य तरीकों (उदाहरण के लिए, मोबाइल ओटीपी) के बारे में जागरुकता काफी कम है: उनके बारे में बताएं।

आधार प्लेटफॉर्म से जुड़ी कानूनी बातें

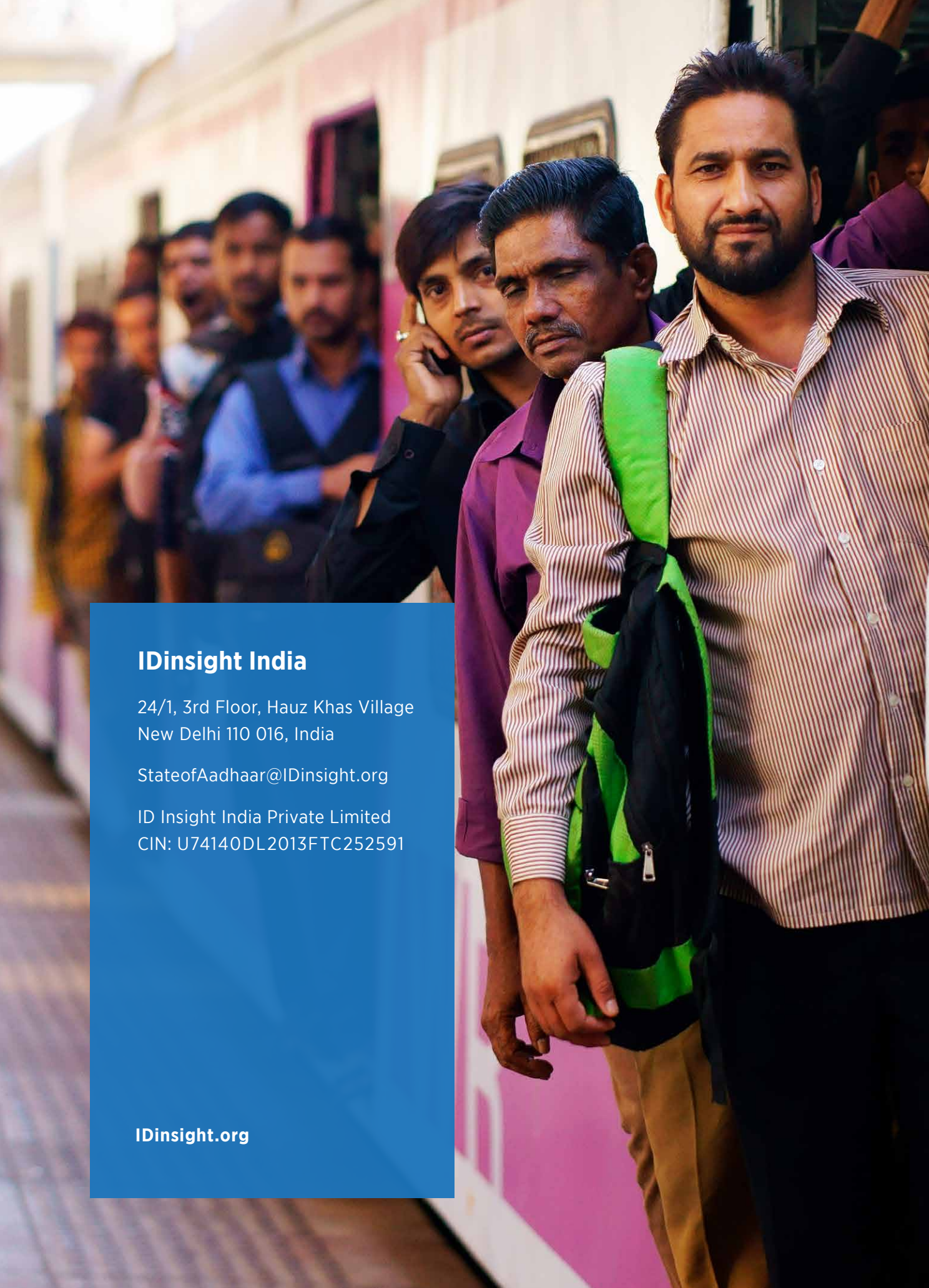
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में साफ़-साफ़ कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक संवैधानिक अधिकार है।

ज़्यादातर भारतीय अपने निजता के अधिकार की परवाह करते हैं; 97 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों ने कहा आधार नंबर की जानकारी देने पर, वह कैसे इस्तेमाल होगी उनके लिए जानना महत्वपूर्ण है।

आधार और टेलिकॉम: प्रमुख बातें

77 प्रतिशत लोगों ने आधार को निजी सेवाओं और मोबाइल से जोड़ने की अनिवार्यता पर सहमति जताई।

50 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों ने, जिन्हें 2016 के आखिरी महीनों में या उसके बाद सिम कार्ड मिला, इस काम के लिए ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया।



IDinsight India

24/1, 3rd Floor, Hauz Khas Village
New Delhi 110 016, India

StateofAadhaar@IDinsight.org

ID Insight India Private Limited
CIN: U74140DL2013FTC252591

IDinsight.org